DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 19 अगस्त 2022 ----DATED----

सील का साया फिर लौटा !

कच्ची कॉलोनियों में कमर्शल प्रॉपर्टियों की नहीं खुलेगी सील

Sudama.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली:** कच्ची कॉलोनियों में जिन लोगों की कमर्शल प्रॉपर्टी सील की गई हैं, उसे मॉनिटरिंग कमिटी ने डी-सील करने से साफ मना कर दिया है। कमिटी के सदस्यों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी कॉलोनियों में रोड न तो मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) और न ही कमर्शल रोड नोटिफाई हैं। ऐसे में इन कॉलोनियों में कमर्शल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ऐसे में कमर्शल प्रॉपर्टी को स्थायी तौर पर डी-सीलिंग का सवाल ही नहीं उठता।

कमिटी के सदस्यों के अनुसार 1700 से अधिक कच्ची कॉलोनियों की लिस्ट रेगूलराइज करने के लिए तैयार की गई है। इन कॉलोनियों में रहने वालों को डीडीए प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी कॉलोनी ही रेगूलराइज हो गई। जिन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है, सिर्फ उनका मकान रेगूलराइज किया गया है। मकान रेगूलराइज होने से ही उस प्रॉपर्टी में कोई कमर्शल एक्टिविटी नहीं कर सकता। कमर्शल गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान-2021 में रोड को या तो मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) या फिर कमर्शल रोड नोटिफाई करना पड़ता है। कच्ची कॉलोनियों में तो किसी रोड को अब तब इस कैटिगरी में अधिसूचित ही नहीं किया गया है। फिर ऐसी कॉलोनियों में तो कमर्शल गतिविधियों का सवाल ही नहीं उठता।

1700 से अधिक कच्ची कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की गई है

सीलिंग के खिलाफ मिले ढेरों आवेदन : मॉनेटरिंग कमिटी के सदस्यों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पर कमर्शल प्रॉपर्टी को डी-सील कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे ढेरों आवेदन कमिटी के पास आए हैं। लेकिन, कमिटी उन आवेदनों पर विचार नहीं करेगी। जबतक कॉलोनी पूरी तरह से रेगूलराइज नहीं हो जाती और रोड नोटिफाई नहीं होती, तबतक ऐसी कॉलोनियों में कमर्शल गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती।

वाटिकाओं पर एमसीडी की टीम द्वारा लगाई गई सील

3 मैरिज वाटिकाएं सील

■ **प्रस, नई दिल्ली : वेस्ट दिल्ली** स्थित जिन मैरिज वाटिकाओं के मालिकों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, एमसीडी ने उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। वेस्ट दिल्ली के बापरौला में दो और उत्तम नगर स्थित चाणक्य प्लेस में एक मैरिज वाटिका सील को सील किया गया है। बापरौला स्थित एक मैरिज वाटिका का प्रॉपर्टी टैक्स 12,69,059 रुपये, दूसरे का 6 लाख और उत्तम नगर के चाणक्य प्लेस स्थित मैरिज वाटिका का 16,93,440 रुपये बकाया है। एमसीडी अफसरों के अनुसार, एमसीडी के सभी 12 जोन में सैकड़ों मैरिज वाटिकाएं चल रही हैं, जिसमें शादी-ब्याह या दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन मैरिज वाटिकाओं से कई लोगों ने 2004 से लेकर अब तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ही नहीं किया है। वाटिका के मालिकों को एमसीडी ने बकाया टैकस भुगतान करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया। लेकिन, ज्यादातर लोगों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। नोटिस जारी करने के बाद भी जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ एमसीडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। एमसीडी अफसरों के अनुसार, बापरौला में आनंद मैरिज वाटिका का 12,69,059 रुपये, सोनम वाटिका का 6 लाख रुपये और चाणक्य प्लेस स्थित मैरिज वाटिका का 16,93,440 रुपये बकाया है।

6 से 16 लाख रुपये तक का बकाया है, एमसीडी ने लिया एक्शन

'जल्द हो रामलीला के लिए ग्राउंड बुकिंग'

■ **प्रस, ईस्ट दिल्ली:** ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के पदाधिकारियों ने डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता से मुलाकात की। महासंघ के पदाधिकारियों ने उनसे रामलीला आयोजन के लिए ग्राउंड की बुकिंग जल्द शुरू कराने के लिए कहा जिससे आयोजक आगे की तैयारियां कर सकें। महासंघ के अध्यक्ष सुरेश बिंदल, महामंत्री भगवत रूस्तगी, कोषाध्यक्ष सतीश लूथरा, श्री रामलीला कमेटी आईपी एक्सटेंशन के प्रमोद अग्रवाल और मदन खत्री ने डीडीए के उपाध्यक्ष के सामने समस्याओं को रखा। उन्होंने डीडीए उपाध्यक्ष से निवेदन किया कि विशेष ध्यान देकर बुकिंग के काम को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने रामलीला महासंघ के नेताओं को भरोसा दिलाया कि उनका पूरा प्रयास रहेगा यह कार्य जल्द शुरू हो जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2022 DATED----------

दिल्ली से मुंबई तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें 12

तीन स्टेशनों के करीब बसेंगी 'कालोनियां'

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली-मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कारिडोर के ऐसे स्टेशनों के आसपास छोटी 'कालोनियां' बसाई जाएंगी, जहां खाली जगह उपलब्ध है। इन कालोनियों में बहुमंजिला आफिस, रिहायशी ब्लाक, स्कूल, अस्पताल, मार्केट, पार्क आदि होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने योजना पर काम शुरू कर दिया है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के तहत निगम फिलहाल राजधानी के तीन स्टेशनों-आनंद विहार, सराय काले खां और जंगपुरा के आसपास कालोनियां विकसित करने की दिशा में काम करेगा। जंगपुरा के लिए तो कंसल्टेंट की नियुक्ति भी हो गई है, जबकि आनंद विहार और सराय काले खां के कंसल्टेंट के लिए टेंडर निकाला गया है।

राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति-2017 के तहत टीओडी के तहत इन तीनों स्टेशनों के आसपास खाली जगह को पर्यावरण अनुकूल, अनिवार्य सुविधाओं से युक्त और पैदल यात्रियों के अनुकूल विकसित करने की योजना है।

शेष ›› पेज 9

आरआरटीएस कारिडोर

- जंगपुरा, सराय काले खां और आनंद विहार स्टेशन के पास होगा निर्माण
- डीडीए संग एनसीआरटीसी बनाएगा बहुमंजिला आफिस, रिहायशी ब्लाक, स्कूल, मार्केट
- जंगपुरा के लिए हो चुकी है कंसल्टेंट की नियुक्ति

पेज तीन का शेष

तीन स्टेशनों के करीब...

इसके निमित्त 'प्रभाव क्षेत्र योजना' (आइजेडपी) बनाई जाएगी। इसे प्रत्येक टीओडी साइट की विशेषताओं और संदर्भ के अनुकूल बनाया जाएगा। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के सुधार कार्यों, जैसे- सड़क चौड़ीकरण (यदि बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए आवश्यक हो), बहु-उपयोगिता वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक सड़कों का उन्नयन, पैदल राहगीरों से जुड़ी सुविधाएं विकसित करना आदि शामिल हैं।

एनसीआरटीसी अधिकारियों ने बताया कि आनंद विहार स्टेशन ट्रांजिट हब भी होगा, क्योंकि यहां रैपिड ट्रेन के साथ बस अड्डा और रेलवे स्टेशन भी है। करीब एक किलोमीटर की दूरी पर कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन भी है। उन्होंने बताया कि कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद तीनों जगह की डीपीआर तैयार कर उस पर स्वीकृति के बाद आगे का काम शुरू होगा।

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि आरआरटीएस कारिडोर तेज गति, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ कारिडोर के क्षेत्र और उसके आसपास निवेश के नए अवसर भी खोलेगा। इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। ट्रांजिट स्टेशनों और कारिडोर के आसपास सघनता आएगी, जिससे नए क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। उन्होंने बताया कि हितधारकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 'प्रभाव क्षेत्र' को विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है।

क्या है टीओडी योजना: टीओडी योजना का उद्देश्य गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को एक ही परिसर में रिहायशी और व्यावसायिक गतिविधियों की सुविधा मिलेगी। एक ही परिसर में आफिस, घर, पार्क से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा होगी, तो लोग निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। योजना के लिए मेट्रो स्टेशन के 500 से 800 मीटर के पास करीब एक हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है। यहां 300 से 500 तक एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) स्वीकृत होगा। इसमें आम लोगों की रिहायश के लिए 30 प्रतिशत, जबकि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 15 प्रतिशत एफएआर होना जरूरी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, AUGUST 19, 2022---DATED---

Govt could enforce regeneration even if threshold isn't achieved

▶Continued from P1

The ministry has proposed a similar obligatory participation of landowners once a sector is notified as eligible for "land pooling". This has been done after the much-hyped policy hardly made any progress since being notified in October 2018. Currently, it's completely voluntary for the landowners to participate in land pooling.

According to the proposed amendments, the Act would specify that DDA can notify policies for land pooling and urban regeneration to give legal backing to the implementation of the schemes.

In a prelude to introducing the urban regeneration scheme, the government has claimed that several existing areas in Delhi have developed over the past more than 100 years and some of them do not meet the norms required for healthy and safe urban habitations. It said these areas can be utilised optimally through redevelopment or urban regeneration. Currently, there is no policy for urban regeneration except in the provisions for redevelopment in the Master Plan for Delhi-2021.

DRAFT AMENDMENTS SAY

The authority or the local body shall take over all land vested in it and may summarily evict occupants from the said land to implement the land pooling or urban regeneration policy. No compensation shall be paid, except as notified in the policy

The process of urban regeneration will be similar to that of land pooling wherein if the voluntary participation of property owners reaches a specified threshold level, then it will be mandatory for rest of the owners to participate.

What may set alarm bells ringing is that the policy spells out that the central government will have the power to direct the DDA or the local body to declare and notify mandatory urban regeneration in identified blocks to ensure time-bound planned regeneration "notwithstanding the fact that minimum threshold of voluntarily participation as specified in the urban regeneration policy may not have been achieved".

The draft amendments, which have been put in the public domain to seek feedback, define urban regeneration as "re-planning, re-construction, re-development, retrofitting, upgradation, rehabilitation, renewal (including amalgamation, pooling and reconstitution of plots) or a combination of these" of an existing developed area, vacant land or lal dora land of an urbanized village wherein landowners and government and private players can participate in the process of urban regeneration.

Sources said after the amendments are approved by Parliament, the DDA will come out with rules specifying the definition of blocks.

According to the draft amendments, the authority or the local body shall take over all land vested in it and may summarily evict occupants from the said land to implement the land pooling or urban regeneration policy. It says no compensation shall be paid "except as notified in the policy".

Govt may order mandatory redevelopment of Delhi areas

Dipak.Dash @timesgroup.com

New Delhi: The housing and urban affairs ministry has proposed major amendments in the Delhi Development Act to give sweeping powers to the central government to direct the DDA or a municipal body to notify any area they identify for mandatory "urban regeneration". Once such an area or "block" is notified, it will be obligatory for all property owners to participate in the redevelopment plan.

The proposed changes may cause a stir since the urban regeneration scheme has been given a wide ambit. It could be applied to developed areas or vacant or lal dora land of an urbanised village. Also, any area that qualifies as "extremely vulnerable to disasters" or "lacks minimum standards of quality of built environment" due to a majority of the building stock being substandard or aged could be taken up for redevelopment, upgradation and renewal. Other areas that may also qualify are "unauthorised constructions and settlements on untenable sites" and inaccessible habitations and land sites.

SWEEPING CHANGES

- Govt will have the power to declare mandatory land pooling even if minimum threshold participation is not achieved
- Authority/local body can direct mandatory urban regeneration for areas vulnerable to disasters
- There will be provision to avoid multiple stamp duty and registration charges on deed of exchanges

The proposed amendment says, "Once a block is notified as eligible for urban regeneration, it shall be obligatory for all land and property owners of the block to mandatorily participate with their land and property in the urban regeneration."

▶Enforce regeneration? P 3

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAM Hindustan Times

NEW DELHI
FRIDAY
AUGUST 19, 2022

{ DELHI DEVELOPMENT ACT }

Centre proposes tweaks to boost urban regeneration

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Union government has proposed amendments to the Delhi Development (DD) Act, 1957, to make way for the implementation of its land pooling policy and urban regeneration in developed areas and unauthorised colonies.

According to the proposed amendments, which were put in the public domain by the Union housing and urban affairs ministry (MoHUA)for pre-legislative consultation on Thursday, if people who own at east 70% of the land in a specified area agree to participate in land pooling, it will be mandatory for all other landowners to also be a part of it.

A senior MoHUA official said the public can send their comments and feedback within 30 days. The ministry announced in March this year that it was going to amend the DD Act.

The proposed amendments will have ramifications for development in large parts of city, and will impact parcels of land available in the rural areas (which have been now declared urbanised), along with redevelopment in unauthorised colonies, said a senior DDA official who asked not to be named.

He added that the amendments will also pave the way for the DDA to become a facilitator instead of its current role as developer. The amendments will also empower the central government to "declare mandatory land pooling and mandatory urban regeneration even if minimum threshold participation has not been achieved", he added.

Mandatory land pooling

The land pooling policy, which was notified twice -- in 2013 and then in 2018 -- is to be implemented in villages located on the outskirts of the city, and aimed at meeting the future housing requirement in the Capital. Close to 1.7 million dwelling units are likely to come up under the policy, according to DDA estimates.

But the policy has been hanging fire mainly due to the clause that made the availability of 70% contiguous land parcels mandatory to create a sector. A sector typically has 100 acres of land. DDA, which currently has 7,317 hectares of land, has been struggling to meet this criterion, as some landowners have been unwilling to give up their land.

Under the proposed amendment, it will be mandatory for landowners to participate in land pooling if the minimum threshold of 70% of contiguous land has not been achieved. Currently, it is not mandatory for any landowners to participate in land pooling or urban regeneration projects.

"It is observed that in many areas where land policy is being implemented, the requirement of 70% contiguity has not been achieved due to non-participation of some land pockets," the ministry officials said. "Provision of mandatory pooling of balance land in a sector or mandatory participation of balance land/ properties in urban regeneration block, where specified threshold has been achieved, in order to facilitate planned urban development," the policy states.

For planned and unauthorised colonies

The policy proposes plan for urban regeneration that will also impact developed areas such as plotted pockets and unauthorised colonies. Under the policy, the government can order mandatory redevelopment in areas where minimum building safety standards are not being met, or where unauthorised construction has come up.

The amendments will empower the government to overcome any reluctance on part of the land owners to participate in any such project.

According to the amendments, "The local body will have the powers to direct mandatory urban regeneration for areas which are vulnerable to disasters, lack minimum standards of built environment, comprise of sub-standard or aged building stock, unauthorised construction and settlements".

Regeneration or redevelopment is a crucial part of the draft Master Plan of Delhi-2041, which is likely to be notified by the end of this year.

Explaining the reason behind concept of regeneration, the ministry said: "Many existing areas in Delhi have developed over the last more than 100 years and some of them do not meet the norms required for healthy and safe urban habitations. These areas can be utilised optimally through redevelopment/ urban regeneration. At present, there is no policy for urban regeneration except the provisions for redevelopment in the Master plan for Delhi (MPD-2021)."

For the urban regeneration policy, mainly in unauthorised colonies, the local bodies will notify blocks to ensure time bound redevelopment. As per the proposed amendment, "The central government, if it so determines as being necessary' under special order, direct the authority or the local body as the case may be, to declare and notify mandatory urban regeneration in identified Blocks to ensure time bound planned Regeneration notwithstanding the fact that minimum threshold of voluntarily participation as specified in the Urban Regeneration Policy may not have been achieved."

Transferable development rights (TDR)

The amendments to the DDA Act will also allow the implementation of Transferable Development Right (TDR), which was introduced for the first time in MPD-2041. Under this, a landowner is given development rights in some other part of the city if they give up a portion of the land for development work, or conservation of heritage properties.

"The development rights of some landowners are restricted due to various reasons like provisioning of green spaces, road network, proximity to monuments' height restriction due to air funnels or power lines, etc," according to the ministry.

Sabyasachi Das, former planning commissioner in-charge at DDA, said the changes were long due as these are necessary for the comprehensive development of the city. "These amendments should have been brought long back. These are essential for planned development of the city. There are so many policies which are not being implemented, as the act didn't have the necessary provisions," he said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, AUGUST 19, 2022

TIMES CITY

Urban Regeneration: Experts Feel Move Lacks Clarity, Ambit Too Wide

Areas Should Have Been Studied, Categorised And Prioritised, They Believe

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: The amendments proposed in the Delhi Development Act, 1957, by the central government aiming at a swifter implementation of the capital's land pooling policy and urban regeneration have divided city planners. While some experts feel that the proposed amendments lack clarity and haven't been properly thought through, others feel that this is a move in the right direction and gives a much-needed push to these policies.

KT Ravindran, urban designer and former chairman, Delhi Urban Art Commission, said that while he hadn't studied the new provisions in detail, the definition for areas where mandatory urban regeneration can be directed is too wide.

According to the notice issued by the Union housing and urban affairs ministry, such areas include those vulnerable to disasters, lacking minimum standards of built environment, comprising sub-standard or aged building stock and unauthorised construction, etc.

Photo for representation

IN FOR GROUNDBREAKING CHANGE OR JUST A PIPEDREAM?

"Ideally there should have been a proper study of such areas and then the areas should have been categorised, prioritised and discussed with the community," said Ravindran. This would have established the parameters under which such areas would fall." He added that such parameters currently exist only for regularisation of unauthorised colonies.

Architect and conservationist AGK Menon said that there were many layers involved in the concept of urban regeneration and unlike land pooling, which he described as a "clean slate", urban regeneration had issues that required a thorough inquiry. The proposed amendments were complicated and "not thought through", he felt.

"As part of urban regeneration, what happens to the existing population? Do they get thrown away?" Menon asked. "All urban villages are ripe for urban regeneration, but do you buy the land and demolish it? This draft is a daydream." He said what happened to the infrastructure existing areas taken up for urban regeneration was worth asking about.

Menon said the concept of urban regeneration was an old one and urban planners thought of it as a strategy, rather than a tool. "The question is why hasn't it worked earlier?" he said.

In contrast, Sabyasachi Das, former planning commissioner, DDA, felt that the proposed amendments were just what the city needed. "It is a very good move and necessary for Delhi," Das said. "In fact, the amendments have come very late. But better late than never."

Das observed that in many areas, if 60% of the residents were willing to pool land for regeneration and 40% weren't, the redevelopment couldn't be undertaken. He pointed out that the Kidwai Nagar area could be redeveloped only because the land belonged to the government.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, AUGUST 20, 2022 ---------DATED----------

New excise policy failed to take off right from outset amid opposition, technical roadblocks

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Excise Policy 2021-22, which promised to change the way alcohol was sold in Delhi, whether in retail shops or in bars and restaurants, failed to ring in the reforms right from the start. While some provisions of the policy — a lower drinking age of 21, bars and restaurants operating till 3am and home delivery of liquor —were not implemented due to political opposition and technical roadblocks, many pockets in the city remained unserved with only around 75% of the promised alcohol shops finally opening.

Even after that, the number of shops kept declining amid opposition from residential and social bodies to selling liquor in their neighbourhoods and due to financial unviability for the zonal licensees.

With the rolling out of the new policy, the government withdrew from the retail business of alcohol. The excise department divided the city in 32 pre-defined zones and auctioned them to private bidders at a huge annual fee. While 31 zones were to have 27 shops each, the IGI Airport was considered as a separate zone with 10 outlets permitted to sell there.

The policy also made opening of two shops mandatory in each ward in 67 non-confirming areas. However, the government made it conditional for the licensees obtain the approval of DDA and the municipal corporation for opening shops in non-conforming areas. "Since no commercial activity is allowed in non-conforming areas, the 67 wards remained without a shop and the bid winner suffered losses," said a government official.

A liquor dealer said he had paid more than Rs 250 crore during the bidding to get the zonal licence to open 27 shops, but could not start more than 15 due to the opposition from residents in some areas and refusal by the municipal corporation to allow liquor trade in non-conforming areas because of restrictions under Delhi Master Plan 2021.

For the first time, the government also allowed the retailers to offer discounts on liquor under the new policy. The hurt the smaller players. "Some of the dealers, who are big players in the industry, offered heavy discounts at their outlets because the wholesale agents they procured the stock from also gave them huge rebates. Since we were not as big, we did not get such rebates from the wholesalers and yet were forced to match the discounts given by the other dealers to stay in business. This affected our business and made it totally unviable to us," he explained.

The closure of shops hurt Delhi government financially and its revenue fell by over 37% in the first quarter of the financial year 2022-23. While the state government had made a budgetary estimate of Rs 2,375 crore as revenue in the first three months of this financial year and Rs 9,500 crore annually, it barely realised Rs 1,485 crore.

Since the Delhi Excise Policy 2021-22 was embroiled in several court cases, the state exchequer could not realise Rs 1062 crore. There was a shortfall of Rs 84.8 crore per month due to the relief given by the high court to liquor stores in non-conforming areas that weren't allowed to operate as this violated the Delhi Master Plan provisions.

HICCUPS

As per Delhi Excise Policy 2021-22

32 Liquor zones created in Delhi	849 Shops had to be opened
27 Shops in 31 zones	10 Shops in airport zone

639 Shops on May 9 were the highest number of shops ever opened

➤ Less than **250 shops** currently operational

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Liquor sector reform, and where it went wrong

Sweta Goswami
sweta.goswami@hindustantimes.com

NEW DELHI: With CBI raids, an FIR accusing 15 people, including deputy chief minister Manish Sisodia, for irregularities and 11 suspensions so far, the Delhi Excise Policy 2021-22 has become the most controversial move of the Aam Aadmi Party (AAP) government in Delhi so far, triggering an intense tussle with the Bharatiya Janata Party (BJP)-led central government.

On Friday, the Central Bureau of Investigation (CBI) raided Sisodia's residence and dozens of other premises across seven states and UTs after registering a case on the alleged irregularities. A look at the policy and why it has ended in controversy.

DELHI EXCISE POLICY, 2021-22: THE KEY POINTS

The 2021-22 excise policy, which came into effect from November 17 last year, was aimed at promoting equitable distribution of the retail liquor business across Delhi. Accordingly, the city was divided into 32 zones with each expected to have 27 liquor shops. It was intended to herald a new era for the city's liquor business by putting an end to cartelisation and black marketing, while also completely overhauling customer experience that was till then marred by dingy stores, a shortage of options in several areas, and a lack of discounts.

The government exited from the retail sale of liquor and rationalised the revenue collections system for both retail and wholesale trade for private players. It made rules flexible for licensees, which also allowed them to offer discounts. The policy also reduced the number of dry days in Delhi from 21 to just three, and allowed bars in hotels, pubs, clubs and restaurants to operate till 3am.

WHAT WENT WRONG?

While several of the plan's proposed targets were met, the policy also had significant hiccups. Liquor traders and restaurateurs have said the policy was not flawed in itself, but its implementation was patchy.

"In a fundamental misconstruct, the size of zones was too big. We repeatedly raised the matter of keeping zone sizes small to reduce financial stakes of the bidders (and increase viability) and to prevent monopolies. But none of that was taken into consideration. We also suggested more simplicity and flexibility in operational issues such as license ownership changes, but to no avail," said Vinod Giri, director general of the Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC).

Eight months into the revamped system, the number of shops fell from 639 in May to 464 in July. The actual plan was to have 849 private retail liquor vends. But the shops never reached that number and customers in some pockets always had to head to other neighbourhoods for their brand of choice, especially those seeking more premium products.

Due to high upfront costs being paid to the government as per the new regime and lower revenue owing to stiff competition and discounts, more and more licensees started exiting the business, leaving at least nine of the 32 zones vacant.

The Delhi Cabinet, led by Kejriwal, in a Cabinet note last month endorsed data that during the first quarter, ₹1,485 crore was realised, which was 37.51% below the budget estimates for 2022-23. Also, a revenue decline on account of surrendered zones was estimated to be around ₹193.95 crore per month, despite no decline in the sale of liquor in Delhi.

The AAP, however, says that the main reason behind the problems was that the former LG Anil Baijal changed a policy clause at the last minute, leading to hundreds of vends not being opened in locations where they would have been set up.

"The policy was approved at the macro level, but not allowed to be implemented properly at the micro level, leading to a lot of license holders exiting," said an AAP functionary who asked not to be named.

WHY IS THE POLICY BEING PROBED?

The controversy began when Delhi chief secretary Naresh Kumar submitted a report to Lieutenant Governor VK Saxena and chief minister Kejriwal citing purported irregularities. To be sure, Kumar was not directed by the LG or the CM to probe the matter but took up the case on his own as the chief secretary is empowered to under the Transaction of Business Rules 1993 to flag deviation from procedures to the LG and the CM.

Based on Kumar's report, LG VK Saxena on July 22 recommended a CBI probe, alleging Sisodia and officials indulged in a series of irregularities to favour private entities in lieu of money. The LG stated that the Delhi government illegally refunded an earnest money deposit (EMD) to a liquor licensee, waived off tendered license fee, violated tender norms by increasing the number of liquor shops in a ward, and took decisions without the Cabinet or the LG's approval.

As per the CS's report, which was included by the LG in his recommendation to the Union home ministry for a CBI probe, the Delhi government's excise department favoured some alcohol merchants by allowing waivers amounting to ₹144.36 crore on license fee they had paid on account of Covid-19 lockdowns. The department refunded a deposit amounting to ₹30 crore to an L-1 bidder who failed to obtain an NOC from the airport authorities, and should have been made to forfeit the payment, the allegations said.

The LG also alleged that the Delhi government, while extending the liquor license of private retails vends, hotels, restaurants and other licensees, did not increase the tendered license fee, which could have been to extend benefits to the licensees. He also stated that extensions for all retail vends were given twice (from April 1, 2022 to May 31, 2022 and then for another month till July 31, 2022) without approval of the Cabinet or the LG.

The CS report also said that the excise department, without seeking approval from the competent authority, revised the formula for calculation of rates of foreign liquor and removed the import pass fee at ₹50 per case on beer, which made foreign liquor as well as beer cheaper for retail licenses at a loss to the exchequer.

The Directorate of Vigilance (DoV), which probed licensees for the CS to prepare his report, said the excise department indulged in cartelisation, awarding tenders to blacklisted companies and illegally allowing manufacturers to get retail licenses by amending the excise policy at will.

AAP says all these allegations are false and trumped-up.

WHAT DOES THE AAP SAY?

On August 6, Sisodia, who is also Delhi's excise minister, said that the Delhi government incurred losses worth "thousands of crores of rupees" under the new excise policy 2021, but blamed this on a decision by the previous LG, Anil Baijal, alleging that he "made a U-turn at the last moment" before implementing the new regime from November 17 last year. Sisodia sought a CBI probe into Baijal's involvement in the matter.

"Under the new excise policy, 849 shops were to be opened across Delhi, including in unauthorised areas. The LG did not object to the proposal and approved it. The file, after making the necessary changes as suggested by the LG, was sent for a second time in November first week. The new policy was to be implemented from November 17 and the LG returned the file on November 15, just 48 hours before the launch, asking us to make major changes to it. The LG said that we need to get permission from the Delhi Development Authority (DDA) and the municipal corporation for permitting liquor shops in unauthorised colonies," Sisodia said.

"Because of this, the Delhi government suffered losses worth thousands of crores of rupees, as close to 300-350 shops that were to open in unauthorised colonies could never operate. As a result, the few companies who managed to open liquor shops in Delhi earned huge profits, while others suffered. The primary aim of the new excise policy was to put an end to the inequitable distribution of liquor shops, which could never be achieved because of the LG's decision," he said.

In government documents, Sisodia also noted last month that the earlier regime, in which large numbers of retail vends were run by government corporations, there were "huge leakages", but accepted that the new regime was indeed hit by instability. "It was also felt that it is not the job of the government to sell liquor. Therefore, the government brought the new excise policy. However, there are several parameters which have caused instability in the new excise policy," read Sisodia's comments in a Cabinet note.

WHAT DID BAIJAL SAY?

On August 9, former LG Anil Baijal hit back at Sisodia and said the allegations were "baseless and motivated".

"It appears that the AAP government of NCT of Delhi and its excise minister [Sisodia] initially claimed record revenue through excise by manipulating figures; but when that got utterly exposed, they are now playing this deplorable game of blaming me, by distorting facts and painting a false narrative," Baijal said in a statement shared by the current LG's office on August 9.

"The record will speak for itself and I dismiss the claims made by the government and its excise minister in toto. Time and investigations will reveal the truth. As a public functionary, I have always worked with the highest degree of moral values and ethics," Baijal said

THE CURRENT SITUATION

The Delhi excise policy 2021-22 has been withdrawn and extended just for a month to prevent a chaotic transition, and to ensure a smooth change to a system where only government-run stores will sell liquor from September 1.

Consumers at present bear the brunt of the controversy, with a mere few shops found open in the city. Stocks too are scarce with premium brands largely being unavailable, forcing people to neighbouring cities to procure liquor.

DELHI EXCISE POLICY 2021-22: A TIMELINE

2021

OCTOBER 1: Govt shuts 580 state-run liquor shops to exit from the retail sale of alcohol

NOVEMBER 17: New excise policy comes into force with 639 of the targeted 849 shops opening

2022

MARCH 31: Policy extended by two months

MAY 31: Policy extended again by two months

JUNE 5: Delhi Excise Policy 2022-23 approved by Delhi Cabinet, but not sent to the lieutenant governor (LG) to date. Kept in abeyance

JULY 8: Delhi chief secretary Naresh Kumar, empowered under the Transaction of Business Rules 1993 to flag any deviation from procedures, submits a report to the LG and chief minister (CM) on the irregularities in the Delhi Excise policy 2021-22

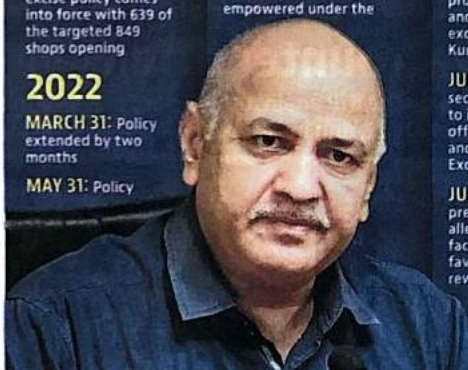

JULY 22: LG VK Saxena recommends that CBI start a probe into the formulation and implementation of the excise policy 2021-22 based on Kumar's report.

JULY 23: LG asks chief secretary (CS) Naresh Kumar to investigate the role of officers in the formulation and implementation of Delhi Excise Policy 2021-22

JULY 25: LG asks CS Kumar to prepare another report on allegations of cartelisation, facilitating monopolies and favouring blacklisted firms in reward of liquor licences

JULY 30, 11AM: Deputy CM Manish Sisodia announces all existing private liquor shops will shut from August 1 (Monday) and only government-run shops will be allowed to open

JULY 30, 9PM: CS Kumar apprises Sisodia and LG of the ensuing liquor crisis due to all shops being shut. A decision is taken to extend the excise policy 2021-22 for a month

AUGUST 6: LG approves the suspension and disciplinary proceedings for "serious lapses" against 11 officers of the state excise department

AUGUST 17: As liquor scarcity continues, with premium brands remaining off the shelf, Delhi excise department prepares for full government operations from September 1 and issues 300 licences

AUGUST 19, 8AM: CBI raids the residence of deputy CM Manish Sisodia and 20 other premises

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 20 अगस्त 2022 ----------DATED----------

डीडी एक्ट में संशोधन से विकास को मिलेगी रफ्तार !

केंद्र सरकार ने इस प्रस्तावित संशोधन पर सभी पक्षों की राय मांगी

सरकार का मानना है कि दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में यह संशोधन इसलिए जरूरी है, क्योंकि सुनियोजित विकास के रास्ते में कई अड़चनें आ रही थीं

NBT नजरिया

वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। यह योजना अगर सही नीयत, समझदारी और सबकी रायशुमारी से लागू होती है तो यकीनन सभी का फायदा है। सही विकास न होने के कारण अभी बहुत सी कॉलोनियों में जलभराव होता है, गंदगी रहती है और लोग बीमार पड़ते हैं। नया प्लान हालात बदल सकता है, बशर्ते उसे लागू करने से पहले एक-एक कदम का तकनीकी सामाजिक पहलू ठीक से समझ लिया जाए।

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

लंबे वक्त के बाद सरकार दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन करने जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार इस संशोधन के लिए तर्क दे रही है कि इससे दिल्ली में सुनियोजित विकास को रफ्तार मिलेगी। इससे न सिर्फ लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने से नए मकान आसानी से बन सकेंगे बल्कि अनाधिकृत कॉलोनियों का भी रीडेवलपमेंट हो सकेगा। हालांकि अभी सरकार ने इस प्रस्तावित संशोधन पर सभी पक्षों की राय मांगी है, लेकिन अगर इसे रूप में संशोधन हुआ तो आने वाले वर्षों में डीडीए के उन फ्लैटों के भी रीडेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा, जो अपनी उम्र पूरी करने जा रहे हैं। इन प्रस्तावित संशोधनों का क्या असर होगा, इस पर पेश है पूनम गौड़ की रिपोर्ट :

क्यों हो रहा है संशोधन

सरकार का मानना है कि यह संशोधन इसलिए जरूरी है, क्योंकि सुनियोजित विकास के रास्ते में कई अड़चनें आ रही थीं। यही वजह थी कि लंबे कवायद के बावजूद अब तक दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी सिरे नहीं चढ़ पा रही। लैंड पूलिंग पॉलिसी नोटिफाई होने के 4 वर्ष बाद भी अब तक सिर्फ 38 फीसदी जमीन ही मिलने की उम्मीद बंधी है।

किस तरह का संशोधन

अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि आवासीय परियोजनाओं के लिए कुछ लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोगों की भी जमीन है, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी में नहीं आ रहे। ऐसे में पूरी योजना ही अधर में लटकी है। एक्ट में यह संशोधन किया जा रहा है कि ऐसे मामलों में अनिवार्य पूलिंग हो। यानी अगर 10 लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं और बीच में एक या दो लोग अपनी भूमि नहीं देते, तो इस संशोधन के बाद उन्हें भी अपनी भूमि देनी होगी।

इसका असर आने वाले समय में अनधिकृत कॉलोनियों पर भी होगा। इन कॉलोनियों को रेडेवलप करने में यह संशोधन मददगार होंगे। दरअसल, दिल्ली में डेढ़ हजार से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इनमें से अधिकांश में सड़कें, गलियां, पार्क, सामुदायिक भवन आदि की सुविधाएं नहीं हैं। इन कॉलोनियों को रीडेवपल करने में भी ये संशोधन असरदार होगा। स्थानीय लोगों में सहमति बनाकर इन कॉलोनियों को नए सिरे से डेवलप किया जा सकेगा।

ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स

ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का भी प्रावधान किया जा रहा है। अगर किसी एरिया में एयर फनल होने, हाईटेंशन लाइन या किसी अन्य वजह से वहां भूमि का पूरा डिवलेपमेंट नहीं हो पाता, तो उसके बदले में और डेवलपमेंट का अधिकार किसी दूसरे इलाके में हो सकेगा।

मसलन, अगर कहीं जमीन के लिए मिले एफएआर के बावजूद निश्चित उंचाई तक इमारत नहीं बना पाते, तो ऐसे लोगों को ट्रांसफरेबल डिवेलपमेंट राइटस (टीडीआर) सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, ताकि उसका फायदा दूसरी जगह मिल सके।

पुराने फ्लैट भी हो सकेंगे रीडेवलप?

हालांकि प्रस्तावित संशोधन में पुराने बहुमंजिला फ्लैटों के रीडेवलपमेंट का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये संशोधन हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में डीडीए और दूसरे बिल्डरों की ओर से बनाए गए ऐसे फ्लैट वाले भी लाभ उठा सकेंगे, जिनके फ्लैट काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। उन फ्लैटों में रहने वालों को एक सीमित खर्च में ही नए फ्लैट मिल पाएंगे।

स्टांप ड्यूटी में भी मिलेगी रियायत

रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया को किफायती रखने के लिए दिल्ली में लागू भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 और पंजीकरण अधिनियम 1908 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के बावजूद लैंड पूलिंग या शहरी रीडेवलपमेंट के उद्देश्य से लेनदेन पर कोई स्टांप शुल्क या पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

'एक्ट में बदलाव जरूरी, लेकिन राह चुनौतीपूर्ण'

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर ने कहा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी रीडेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इन बदलावों के लागू होने के बाद रीडेवलपमेंट के काम में सबसे बड़ी अड़चन भूमि अधिग्रहण को दूर किया जा सकेगा। इन बदलावों का राजधानी पर कैसा असर होगा? इस पर डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर सब्यसाची दास से एनबीटी ने बात की।

डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर सब्यसाची दास के अनुसार, अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं, वह रीडेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी हैं। इस प्रक्रिया में पहले ही करीब 10 सालों की देरी हो चुकी है। इन बदलावों के लिए रीडेवलपमेंट के कितने भी प्लान बना लें, वह सिरे नहीं चढ़ पाएंगे। जमीन आज सबसे बड़ी समस्या है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए यह बदलाव होने ही चाहिए। लोग रीडेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लेते। इसी वजह से अनधिकृत और पुराने बसे एरिया के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। राजधानी में लोग सालों से एक ही जगह में रह रहे होते हैं। उनकी भावनाएं भी वहां से जुड़ी होती हैं और यह उनकी कमाई का जरिया भी होता है। इसलिए सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। पश्चिमी देशों में लोग इसके लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। लैंड पूलिंग में भी यही समस्या आ रही है। कुछ लोग जमीन देना नहीं चाहते। इसलिए वह लैंड पूलिंग में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से पूरी पॉलिसी अटक गई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी पर 2013 में काम शुरू हुआ था। टीओडी(ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पर 6 साल पहले काम शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि यह इतना आसान भी नहीं होगा। पब्लिक नोटिस आने के बाद ही इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, पब्लिक हियरिंग होगी। उसमें भी लोग विरोध जताएंगे। वहीं, इसे लेकर लोग कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं।

कोर्ट में यह मामला कितना लंबा चलेगा यह भी देखना होगा। एक्ट में बदलाव की प्रक्रिया संसद में होकर गुजरती है। एक्ट को संसद से पास करवाना जरूरी होता है। एक्ट के बाद इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाने होंगे।

अड़चन होगी दूर

- उन्होंने कहा, इन बदलावों के लागू होने के बाद रीडेवलपमेंट के काम में सबसे बड़ी अड़चन भूमि अधिग्रहण को दूर किया जा सकेगा
- जमीन आज सबसे बड़ी समस्या है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए यह बदलाव होने ही चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI *
AUGUST 21, 2022

Bidhuri: Register case against CM, ministers for violating master plan

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: BJP urged the Central Bureau of Investigation on Saturday to register a case against chief minister Arvind Kejriwal and his ministers for violating the provisions of the Delhi Master Plan 2021 by allowing the opening of liquor shops in non-conforming areas through a cabinet decision.

Addressing a press conference, Ramvir Singh Bidhuri, leader of the Opposition in Delhi Assembly, alleged that in a meeting chaired by Kejriwal on November 5 last year, the council of ministers took a decision to permit zonal licensees to operate liquor shops in non-conforming areas.

"The cabinet has no power to permit opening liquor shops in non-conforming and residential areas. It is a violation of Delhi Master Plan. I demand the registration of an FIR against Kejriwal and his ministers who were present at the meeting by CBI," said Bidhuri.

No immediate reaction was available from the AAP government.

Bidhuri, who is the MLA from Badarpur, claimed that necessary amendments should have been made in the Delhi Master Plan to allow liquor shops to operate in non-conforming areas.

> **Bidhuri said the cabinet had no power to permit opening of liquor shops in residential & non-conforming areas**

Deputy chief minister Manish Sisodia had earlier alleged that former lieutenant governor Anil Baijal had made it mandatory for liquor licensees to seek approval of DDA and the municipal corporation for liquor shops to function in non-conforming areas just two days before they were to open on November 17, 2021 to "benefit a few licensees". He also claimed that the LG's stipulations caused a loss of thousands of crores of rupees to the state exchequer, adding that the Excise Policy 2021-22 would have earned a revenue of Rs 10,000 crore had this condition not been incorporated in the policy.

Baijal reacted to these allegations by accusing Sisodia of "perpetrating blatant lies and falsehoods to save his own skin".

Bidhuri said that the cabinet took the decision to allow liquor vends in non-conforming areas on November 5, 2021 and the former LG approved the decision on November 15, making it conditional on the excise department or the licensee obtaining the approval of DDA and MCD.

HC issues contempt notice to resident on floodplain eviction

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court has initiated contempt proceedings against a petitioner for hiding full facts from it in a matter related to the demolition of a slum cluster.

The court found that while seeking its intervention, the petitioner didn't inform that the Supreme Court had dismissed a similar plea filed by his father relating to slum dwellings on the Yamuna floodplain at Bela Estate near Rajghat. The high court issued a show cause notice of contempt to Randheer, directing him to explain why he should not be hauled up for contempt.

Randheer and 18 others have moved high court against Delhi Police and other public authorities, challenging the proposed demolition drive.

According to the plea, some policemen, along with the SHO of Daryaganj police station, landed at Moolchand Basti on August 12, 2022 and threatened the slum dwellers that immediately after August 15, there would be a demolition drive in the area and the residents should themselves leave the jhuggis.

However, Delhi Development Authority (DDA) informed the court that the area had been declared part of the Yamuna floodplain and there were various injunctions and orders by courts to remove encroachments. DDA also highlighted petitions that were filed before the Supreme Court, indicating that the fathers of some of the 19 petitioners had gone to the apex court and lost, but this fact had not been disclosed in the present proceedings. "Consequently, let the petitioner show cause why proceedings in criminal contempt be not drawn against them," the high court said.

The bench also noted that the DDA counsel had placed for its examination the two decisions of the high court itself to contend that identical challenges had been dismissed also by this court. On the other hand, the petitioners maintained that the cases mentioned were of landownership, but the present case was about right to reside and not be evicted.

Book honours city's unsung fighters for freedom

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor V K Saxena on Saturday released a book on relatively lesser known revolutionaries from Delhi who had made sacrifices in the freedom struggle between 1857 and 1947.

The book, Delhi in the Era of Revolutionaries, 1857-1947, has been written by Bhuvan Lall, who earlier penned a biography of Netaji Subhash Chandra Bose.

Saxena , earlier this week, dedicated 16 major DDA Parks in the city to the memories of these freedom fighters. Among those present at the book launch at Raj Niwas were the 94-year-old granddaughter of Lala Hardayal, great granddaughter of General Shah Nawaz Khan and relatives of other freedom fighters.

The LG announced that Delhi would soon have a memorial or a museum dedicated to the unsung heroes of Delhi. He said the entire generations after Independence had grown up knowing just a few names as icons of the freedom struggle and 75 years of Independence was the right time to acknowledge and remember these lesser known heroes. "Their names needed to be etched and chronicled in our contemporary history for posterity to see and celebrate," he said.

Saxena appealed to the citizens to work towards changing Delhi for better and dedicate themselves to make India the most advanced country when 100 years of Independence are celebrated in 2047.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2022 ----------DATED----------

आशोक विहार के खोजा वाला पार्क में बनेगा विश्वस्तरीय उद्यान

उपराज्यपाल ने छह माह में काम पूरा करने का दिया आदेश, राजधानी का होगा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, पर्यावरण को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: अशोक विहार के खोजा वाला पार्क में विश्व स्तरीय उद्यान विकसित करने का काम छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 27 मई को अधिकारियों के साथ इस पार्क का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नगर निगम के सहयोग से इसे विकसित करेगा। यह उद्यान राजधानी में इको-टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनेगा।

विदेशी और दुर्लभ पौधे यहां मिलेंगे इस उद्यान नर्सरी में स्थानीय प्रजाति के साथ-साथ विदेशी और दुर्लभ किस्म के पौधे भी तैयार होंगे। यहां से पौधे सरकारी विभागों के साथ ही आम नागरिकों को भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन के लिहाज से भी इसे एक आकर्षक जगह के तौर पर तैयार किया जाएगा। यह जगह वजीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है, इसलिए इस पूरी जगह को हरा-भरा बनाने से पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। प्रदूषण में भी कमी आएगी।

छह भाग में विभाजित होगा पार्क: इस पार्क को दो उपवन, आंगन, शिक्षण, रक्षण और मंदार में विभाजित किया जाएगा। उपवन को शहरी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ओपन जिम और खेलने का स्थान होगा। आंगन में नवग्रह प्लाज, कैफेटेरिया, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग, शौचालय, तालाब, बच्चों के खेलने का स्थान आदि बनेगा। शिक्षण क्षेत्र में सामुदायिक सहयोग से सीखने को बढ़ावा दिया जाएगा। यहां इको बाजार, सामान बेचने के काउंटर, कार्यक्रम के लिए जगह विकसित की जाएगी। रक्षण क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, तितली गार्डन आदि बनेगा। मंदार में उद्यान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 21 अगस्त 2022

नई एक्साइज पॉलिसी गैरकानूनी थी, पूरी कैबिनेट ही जिम्मेदार : बीजेपी

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर शनिवार को भी बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि यह पॉलिसी गैरकानूनी थी और इसके लिए पूरी कैबिनेट ही जिम्मेदार है। उनका कहना था कि 5 नवंबर, 2021 को इस पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी। पॉलिसी में यह उल्लेख है कि कहीं भी शराब की दुकानें खोली जा सकती है। यहां तक की रिहायशी इलाकों में भी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली कैबिनेट इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम ही नहीं थी, क्योंकि मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के मुताबिक नॉन-कन्फॉर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोली ही नहीं जा सकती हैं। अगर पॉलिसी में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाते हैं, तो मास्टर प्लान में संशोधन करना पड़ेगा। इसे डीडीए और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही नोटिफाई किया जा सकता है।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, स्कूलों में कमरे बनाने में भी कई गड़बड़ियां हुई

बिधूड़ी ने मांग की कि एक्साइज पॉलिसी पर विचार-विमर्श के लिए दिल्ली सरकार तुरंत ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाए। वहीं, वेस्ट दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेताओं अपने करीबियों को शराब के लाइसेंस दि और इसमें करोड़ों की गड़बड़ी की गई पब चलाने वालों को भी नई शराब नीति के तहत करोड़ों रुपये के लाभ पहुंचाए गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022 दैनिक जागरण ----------DATED----------

'वसंत उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दें'

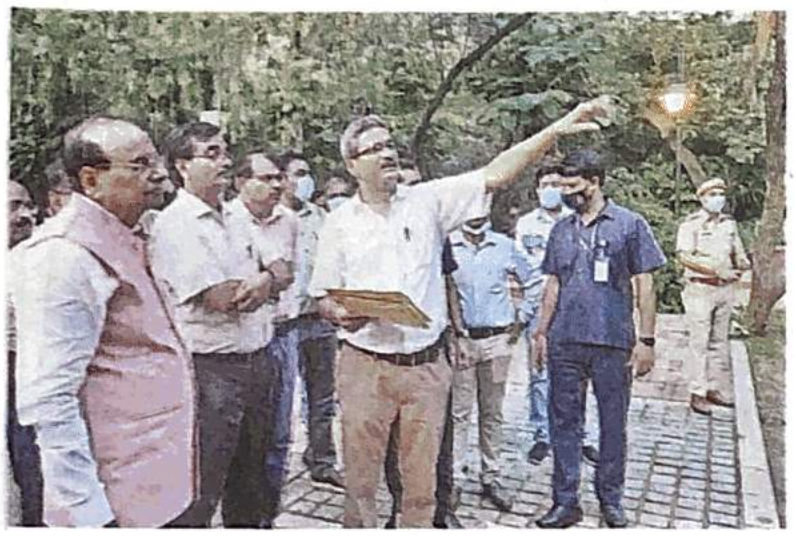

वसंत उद्यान का निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना (बाएं) ● सौजन्य-राजनिवास

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को वसंत विहार में वसंत उद्यान का दौरा कर पार्क में किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान एलजी ने निर्देश दिया कि पार्क के एंफीथिएटर क्षेत्र में और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों और अदाकारों को पार्क में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डीडीए इन कलाकारों से सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क वसूल न करे।

वसंत उद्यान पार्क, जिसे बाग-ए-बहार के नाम से भी जाना जाता है, का पुनर्विकास कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। पार्क को इंडिया पवेलियन, लंदन बिनाले 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था, जो दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी और कल्पनाशील डिजाइनरों, क्यूरेटरों और डिजाइन संस्थानों की वैश्विक सभा है। 43.17 एकड़ में फैले इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न उपकरणों से युक्त प्ले एरिया, ओपन जिम, पापअप सिंचाई प्रणाली, आम जनता के लिए सुविधा, बगीचे की लालटेन व सीसीटीवी की सुविधा है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुरक्षा उपायों के साथ पुरातत्व विभाग, जीएनसीटीडी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्मारक के बारादरी क्षेत्र का पता लगाने के लिए भी कहा।

एलजी ने साइबर सेल मुख्यालय के कामकाज का लिया जायजा

जासं, नई दिल्ली: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को द्वारका स्थित इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक आपरेशंस यूनिट और नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का दौरा कर पुलिसकर्मियों के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फोरेंसिक उपकरणों के काम करने के तरीके, डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी फोरेंसिक के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर सक्सेना ने पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत की और दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय के आदर्श वाक्य को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और उन्नत करना है, ताकि दिल्ली के लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि आइएफएसओ यूनिट अपनी नवीनतम तकनीकी क्षमताओं के साथ किसी भी साइबर अपराध के बारे में पता लगाने में सक्षम है। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व विशेष आयुक्त रविंद्र यादव समेत दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्तान

एलजी ने डीडीए पार्क का निरीक्षण किया

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दक्षिणी दिल्ली स्थित वसंत पार्क में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। उपराज्यपाल शनिवार को पार्क से जुड़ी विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। एलजी ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को बिना किसी शुल्क के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमित दी जाए।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 22 अगस्त 2022

'बाग-ए-बहार' में फ्री में कार्यक्रम कर सकेंगे स्थानीय कलाकार

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

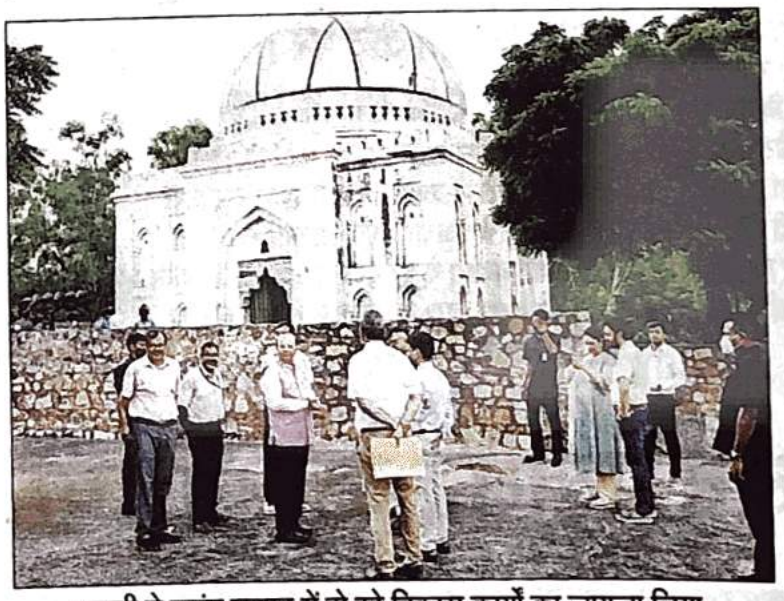

एलजी ने वसंत उद्यान में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया

वसंत उद्यान (बाग-ए-बहार) में अब अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्थानीय कलाकारों से कोई फीस न लेकर उन्हें यहां कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। एलजी और डीडीए अध्यक्ष वी. के. सक्सेना ने डीडीए को यह निर्देश दिए हैं। एलजी 20 अगस्त को वसंत विहार स्थित वसंत उद्यान का निरीक्षण करने गए थे। उन्होंने वसंत उद्यान में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्क के एंफीथिएटर में अधिक से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। इसमें उन्होंने स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए से कहा कि ऐसे कलाकारों से वसंत उद्यान में कोई चार्ज न लिया जाए। वसंत उद्यान तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस पार्क का रीडिवेलपमेंट 2020 में ही पूरा हो गया था। पार्क को इंडिया पवेलियन, लंदन डिजाइन बिएनेल-2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। इसमें दुनिया भर के डिजाइन इंस्टीट्यूट, डिजाइनर और क्यूरेटर्स ने हिस्सा लिया था। यह पार्क 43.39 एकड़ में है और यहां बच्चों के लिए प्ले एरिया, ओपन जिम, सिंचाई सिस्टम, पब्लिक से जुड़ी जनसुविधाएं, विभिन्न प्रकार की लाइटें, गार्डन लालटेन आदि की सुविधाएं हैं। सुरक्षा के लिए पार्क में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

> एलजी ने डीडीए को पार्क में ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा

एलजी ने यहां के ग्रीन एरिया और एतिहासिक धरोहरों के रखरखाव और विकास की तारीफ की। एलजी ने यह भी कहा कि यहां की ऐतिहासिक इमारत के बारादरी क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संभावनाओं को पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर तलाशें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS... THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, AUGUST 22, 2022 ...DATED...

Sisodia: 'Scam' amount has shrunk from ₹8,000cr to ₹1cr, let CBI probe

Atul Mathur & Sidhartha Roy | TNN

New Delhi: Deputy chief minister Manish Sisodia on Sunday said he welcomed the CBI probe against him but the investigating agency should "fairly probe" his complaint too.

Sisodia had written to the CBI earlier this month that the former LG had made a U-turn on the excise policy and made it mandatory for liquor licensees to take permission from MCD and DDA to open shops in non-conforming areas. While Sisodia alleged that the move caused the government a loss of thousands of crores of rupees, the then LG, Anil Baijal, has accused him of "perpetrating blatant lies and falsehoods to save his own skin".

The deputy CM, who holds the charge of 18 departments, said if the BJP-led central government was really interested in getting complaints of corruption investigated by the CBI, it should also probe his charges against the LG.

The minister added that "fictitious" amounts were being floated in the market by the BJP which had no relevance. "They first said it was a Rs 8,000-crore scam, then said it was a Rs 1,100-crore scam and then gave a figure of Rs 144 crore. The figure got reduced to Rs 30 crore. The FIR, however, says it is a Rs 1-crore scam. I am open to being investigated, I have nothing to hide. I guarantee that all allegations will turn out to be fake," he said.

The deputy CM said that if corruption was an issue, the Centre would have got the construction of the Bundelkhand expressway, which caved in within five days of its inauguration, or sale of spurious liquor in Gujarat, which saw hundreds of deaths in 27 years, probed. "They are not interested in stopping corruption or preventing spurious liquor deaths. They are interested in Arvind Kejriwal. Their motive is to put Kejriwal's ministers in jail," Sisodia said.

Sanjeev Rastogi

Talking about the raid at his residence, Manish Sisodia said the CBI team thoroughly searched every room of his house and looked through every bed and almirah, mattress and pillow, sarees and clothes

The deputy CM reiterated that his government will not stop working. He said the BJP fears Kejriwal because despite harassment for seven years, the Delhi CM did not stop working. "He is a man committed to the welfare of people. He didn't stop when one of his ministers (Satyendar Jain) was jailed. He won't stop if another minister is jailed too," he added.

Talking about the party's expansion nationally, Sisodia said it was now the wish of 130 crore people of the country to see Kejriwal as Prime Minister. Whether AAP goes alone in the 2024 elections or forms an alliance with other parties was not the question, he added.

"There is one person who is busy in conspiracies, misusing CBI-ED and destabilising state governments while there is another who is diligently working all the time. People want to give Kejriwal a chance. It started with five years to Kejriwal in Delhi and moved to Punjab with the idea of one opportunity to Kejriwal. It is now the wish of 130 crore people to give Kejriwal a chance," he said.

Talking about the raid at his residence, Sisodia said the CBI team thoroughly searched every room of his house and looked through every bed and almirah, mattress and pillow, sarees and clothes. "See, it is their job. If you send a team, it will search everything. I don't mind that," he said.

In retrospect, does he miss his days of social activism? "There is a limit to what you can do as an activist. It reached a saturation point, and after that we could only write books or research papers but wouldn't have been able to do anything to bring about a change. That's why we entered politics and have worked for seven years now to test its limits," he said.

How's his family taking it? "They are human, it impacts them. This is unfortunate. But we have to fight it together," he said.

LG for more events at S Delhi park

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Sunday directed the Delhi Development Authority to promote more cultural programmes and events in Vasant Udyan (Bagh-e-Bahar), a park developed by it in south Delhi's Vasant Vihar.

During a visit to review development work being carried out at the park, Saxena directed that local artists and performers should be encouraged to perform in the amphitheatre. He also directed DDA not to charge these artists for using the facilities, the authority said in a statement.

DDA said Vasant Udyan is a prestigious park of the authority and boasts of all the facilities. The redevelopment work of the park was completed in 2020, it said in the statement. The park was selected for exhibition at India Pavilion, London Biennale 2021, which is a global gathering of the world's most ambitious and imaginative designers, curators and design institutes. Spread over 43.1 acres, the park has facilities like children play area with equipment, open gym, pop-up irrigation system, public convenience, different types of lights, including garden lantern, CCTV cameras, etc. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI NAME OF NEWSPAPERS--- THE HINDU DELHI FRIDAY, AUGUST 19, 2022 ----------DATED ▸ 19 अगस्त, 2022 ▸ शुक्रवार

रामलीलाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग की मांग

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष सुरेश बिंदल ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपसभापति मनीष गुप्ता एवं मेंबर इंजीनियर डीसी गोयल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष के साथ महामंत्री भगवत रुस्तगी कोषाध्यक्ष सतीश लूथरा भी मौजूद रहे। दरअसल, ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ की ओर से बताया गया कि 20 छोटी व बड़ी रामलीला का आयोजन डीडीए के ग्राउंड पर आयोजित किया जाता है। रामलीला अगले माह से शुरू होगी। हालांकि अभी तक रामलीला के मंचन के लिए डीडीए के ग्राउंड की बुकिंग शुरू नहीं हुई है। जिसे लेकर डीडीए के उपसभापति से मुलाकात कर ऑनलाइन बुकिंग को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है। रामलीला महासंघ के महामंत्री भगवत रुस्तगी ने बताया कि मुलाकात बहुत अच्छी रही है। हमने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। डीडीए के उपसभापति ने मनीष गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द कार्य हो जाए। उन्होंने कहा कि सोमवार तक डीडीए ग्राउंड की बुकिंग की व्यवस्था शुरु हो जाएगी।

Union Ministry shares proposed amendments to boost land pooling

Part of 'pre-legislative consultation'

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

The Union Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) on Thursday placed the proposed amendments to the Delhi Development Act, 1957, on its website for public feedback and comments.

One of the proposed amendments is to make land pooling mandatory in areas where a minimum of 70% of landowners agree to pool in their land parcels. However, another amendment looks to give powers to the Centre to declare pooling mandatory, even if the minimum threshold is not achieved.

According to a notice issued by MoHUA, dated August 18, the decision comes as part of a "pre-legislative consultation" with the public and the stakeholders over the next 30 days.

The proposed amendments – which were announced by Union Minister Hardeep Puri on March 8 – are aimed at eliminating roadblocks in the Delhi Development Authority's (DDA) Land Pooling Policy (LPP), in which the urban body plays the role of a facilitator.

In its notice, the MoHUA highlighted that as of July 27, a total of 6973 applicants, with 7,317 hectares of land, have expressed interest in the LPP. However, this area is only 38.36% of the total land (19,074 hectares) that has been earmarked for land pooling.

The LPP looks to provide 17 lakh dwelling units – including five lakh units for the economically weaker sections – for a population of roughly 80 lakh people.

The MoHUA in its notice stated that in its present shape, the LPP does "not address many key issues like compulsory land pooling for optimal planning, conferment of land title after redistribution of land and clarity about the levying of stamp duty on redistribution of land among other issues."

Though the DDA has stated that it has achieved the minimum participation rate in various sectors, the other condition – 70% of contiguous land is required to attain eligibility for forming a landowners' consortium in a sector – is yet to be fulfilled, because of which no development work has been carried out since the policy was first notified back in 2013.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SUNDAY, 21 AUGUST, 2022 | NEW DELHI

AMID EXCISE POLICY ROW

Panel set up by ex-LG Baijal to file report on non-conforming areas

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Amid the storm over the CBI probe and raids over the alleged irregularities in the Kejriwal government's excise policy 2021-22, a committee is soon likely to submit its report on the issue of liquor vends in non-confirming areas of the city. The five-member committee was formed in April by then Lieutenant Governor Anil Baijal on the High Court's order to draw up a list of conforming and non-conforming municipal wards in the city.

Deputy Chief Minister Manish Sisodia, named an accused in an FIR registered by the CBI probing alleged irregularities in the Excise Policy execution, has alleged Baijal obstructed opening of liquor stores in non-confirming areas.

Baijal had hit back at Sisodia, calling him a "desperate man" and alleging he was trying to save his "own skin". He had asserted no rules allowed opening liquor vends in non-confirming areas of the city.

"We are finalising the report and it is expected to be filed in the High Court very soon," said a member of the committee. The five-member committee chaired by excise commissioner of Delhi included DDA and MCD officials as its members.

It was mandated to "examine the factual position prevailing in different wards and localities so that an authoritative list of conforming and non-conforming wards was prepared after the due verification", officials said.

The committee in its report is likely to recommend opening liquor vends in confirming parts bordering non-confirming areas so liquor consumers living there too have easy access to it, a source claimed.

The Delhi Cabinet in its meeting on November 5, 2021 had decided to allow opening of liquor shops in non-confirming areas too.

When the zonal licencees failed to open liquor vends due to restriction of the Delhi Development Authority and MCD permission, a committee was formed by Baijal under the chairmanship of the vice chairman of DDA to find a solution.

That committee had recommended in December 2021 shifting retail licensees from nonconfirming wards to conforming wards in a zone.

However, the issues persisted and Sisodia has claimed the government suffered revenue losses of thousands crores of rupees because shops could not open in non conforming areas as some zonal licensees whose all wards were confirming had a windfall gain.

The second committee headed by excise commissioner was supposed to submit its report by May 31.

A report prepared by Vigilance Directorate on the role of excise officials in executing the policy observed that the Committee report was not submitted by the then excise commissioner A Gopi Krishna despite having the draft ready with him on July 4.

Krishna is also one of the accused in the FIR and one of the 11 Excise officials whose suspension was recommended by the current LG VK Saxena.

Saxena last month had recommended the CBI probe into the alleged violations of rules and procedural lapses in implementing the Excise Policy 2021.

पंजाब केसरी DELHI 21 अगस्त, 2022 ▶ रविवार

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: महिला को भूखंड सौंपने का आदेश

30 वर्षों से अधिक समय तक महिला को परेशान करने पर डीडीए पर जुर्माना

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने 1991 में एक भूखंड के आवंटन के लिए अपना पंजीकरण कराने वाली एक महिला को 30 सालों से अधिक समय तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा परेशान किए जाने और उसके उदासीन रवैये को लेकर डीडीए को फटकार लगाई है। बता दें कि महिला को इस भूखंड का कब्जा नहीं मिल पाया है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने एक सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डीडीए की अपील खारिज कर दी। साथ ही, उसे महिला को भूखंड सौंपने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि प्राधिकरण का रवैया पूरी तरह से गैर-पेशेवर और अक्षम्य है तथा वह डीडीए पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की इच्छुक है। बेंच ने इस बात का जिक्र किया कि महिला ने डीडीए को अपना पैसा वापस करने को कहा था और उसके द्वारा प्राधिकारियों को सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद डीडीए ने मूल मांग सह-आवंटन और अन्य दस्तावेज मांगे। बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि डीडीए का उदासीन रवैया, गैर-पेशेवर व्यवहार अक्षम्य है।

खास बातें...

- सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डीडीए की अपील की खारिज

बेंच ने कहा कि इस मामले के तथ्य डीडीए के हाथों एक महिला को सिर्फ परेशान किए जाने को प्रदर्शित करते हैं। बेंच ने कहा कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि एक नोटिस जारी किया गया था, जबकि डीडीए ने ऐसा दावा किया है। बेंच ने कहा कि साथ ही सिंगल बेंच के जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि डीडीए ने अपनी फाइल खो दी है।

'गुमनाम नायकों लिए बनेगा संग्रहालय'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को राजनिवास में स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के गुमनाम व अनसुने योद्धाओं

की स्मृति में समर्पित "दिल्ली इन द ऐरा ऑफ रिवोल्यूशनरीज, 1857-1947" पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप एवं आजादी के अमृत महोत्सव काल में यह पुस्तक दिल्ली के उन वीर और महान बेटों और बेटियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान की गाथा बताएगी जिन्होंने देश की आजादी के लिये अथक प्रयास किये व अनेक बलिदान दिये। स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों- पोते-पोतियों के बीच लोकार्पित की गई यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक और मीडिया उद्यमी डॉ भुवन लाल द्वारा लिखी गयी है। इस अवसर पर एलजी ने घोषणा की कि दिल्ली में जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों का एक स्मारक/संग्रहालय स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारे समकालीन इतिहास में इन गुमनाम नायकों को उकेरने और लिपिबद्ध करने की जरूरत है ताकि भावी पीढ़ी इनके बारे में जान सके। इससे पहले एलजी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में 16 प्रमुख डीडीए पार्कों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर समर्पित किया था। उपस्थित लोगों में लाला हरदयाल की 94 वर्षीय पोती, जनरल शाहनवाज खान की परपोती, दिल्ली से जुड़े अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के अलावा मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- DELHI THE HINDU SUNDAY, AUGUST 21, 2022 ---------DATED----------

CBI raids a clean chit from Modi govt.: AAP

Party leaders say officials returned empty-handed even as BJP, Cong. demand CM, Dy. CM's resignation

STAFF REPORTER
NEW DELHI

A day after the Central Bureau of Investigation (CBI) conducted searches at Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence, AAP leaders said the agency sleuths returned "empty-handed" and termed the exercise a "total failure".

AAP MLA Saurabh Bharadwaj said the exercise was a "clean chit from the Narendra Modi government".

"We don't have a problem with the CBI officers. They are doing their duty, it is their job. They will have to do whatever the Central government asks them to do. Earlier, it was the UPA [United Progressive Alliance] that misused its power, now it is the BJP. We all remember how Prime Minister Modi used to go around harping about the misuse of the CBI when he was on the other side," said Mr. Bharadwaj.

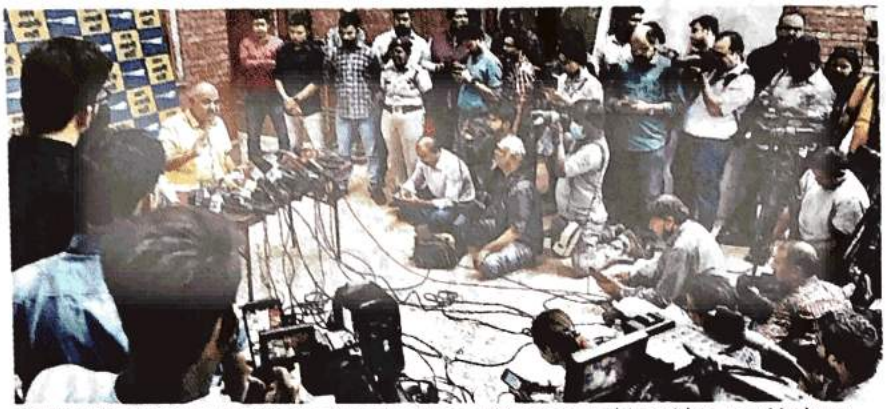

Deputy Chief Minister Manish Sisodia addressing mediapersons at his residence on Mathura Road in New Delhi on Saturday. • SHIV KUMAR PUSHPAKAR

The CBI conducted raids at 31 locations, including the residences of Mr. Sisodia and Delhi's former Excise Commissioner Arava Gopi Krishna, across six States and one Union Territory on Friday after it registered an FIR in connection with the AAP government's excise policy, which was rolled out in November last year.

Demand for session

Hitting out at AAP, Leader of the Opposition in the Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri said the excise policy was "completely illegal" and demanded that the city government immediately convene an Assembly session to discuss "the scam".

Meanwhile, Delhi Congress leaders and workers staged a protest outside the AAP's office on Saturday, demanding the resignation of Mr. Sisodia in connection with the alleged irregularities in the excise policy.

The protesters marched from the Delhi Congress office at DDU Marg towards the AAP headquarters.

Mr. Bidhuri also demanded Chief Minister Arvind Kejriwal's resignation saying "he was aware of the policy being illegal and was responsible for its execution".

"Permission was given to open liquor shops in non-conforming and residential areas. The Delhi Cabinet had no right to provide such approvals as the Master Plan-2021 does not allow it. There is a process for changes in the master plan and they are notified only after the approval of the DDA and the Ministry of Housing and Urban Affairs. But the Delhi Cabinet deliberately violated the rules of the master plan," said Mr. Bidhuri.

sunday pioneer

Bidhuri demands Monsoon Session to discuss excise policy

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Leader of the Opposition in the Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri on Saturday demanded that the Monsoon Session of the Assembly be called to discuss the excise policy and said that Chief Minister Arvind Kejriwal should tell people why permission was given to open liquor vends in non-conforming areas.

"The Government will have to explain why it deliberately ignored the rules of the master plan," Bidhuri said while addressing a press conference at the party headquarters.

"The Kejriwal Government allowed liquor vends to open in non-conforming areas, which is a clear violation of the Master Plan of Delhi-2021. The new excise policy was illegal and unconstitutional. Delhi Cabinet approved the new excise policy on 5 November 2021. Chief Minister Arvind Kejriwal presided over this cabinet meeting. It was said in the excise policy that liquor shops can be opened anywhere in Delhi.

Even permission was given to open liquor shops in non-conforming and residential areas too. The Delhi cabinet had no right to provide such approvals as liquor shops cannot be opened in non-conforming areas as the Master Plan-2021 does not allow it," Bidhuri said.

The BJP leader further said that there is a complete process for changes in the master plan and it is notified only after approval by the DDA and the Ministry of Housing and urban affairs. But the Delhi cabinet deliberately violated the rules of the master plan. Therefore, the entire cabinet, including CM Kejriwal is liable for the violation of rules and procedural lapses. Hitting out at Kejriwal, Bidhuri said that the Chief Minister had said that the new excise policy will boost the revenue by Rs 10,000 crore.

"While the liquor sales have gone up in the city, the government's revenue from it hasn't. Why so? We want the government to call the monsoon session to discuss the excise policy and all the scams in various departments such as DTC (Delhi Transport Corporation), water (Delhi Jal Board), ration (food supplies department) and making hospitals on papers.

This Government, which came into power in the name of removing corruption, has been thoroughly exposed now and needs to answer the questions of the public".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
'CE
NAME OF NE\ ... TED--------------------

the pioneer
NEW DELHI | MONDAY | AUGUST 22, 2022

'Promote more cultural events at Vasant Udyan'

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Sunday visited the Vasant Udyan in Vasant Vihar directed officials to organise cultural events in the amphitheatre area of the park to encourage local artists and performers.

During the visit, Saxena directed that the Delhi Development Authority (DDA) does not charge these artists for using the facilities. Vasant Udyan park at Vasant Vihar also known as Bagh-e-Bahar, is a prestigious park of DDA with all the modern facilities.

The redevelopment work of the park was completed in the year 2020. The park was selected for exhibiting at India Pavilion, London Biennale 2021, which is a global gathering of the world's most ambitious and imaginative designers, curators and design institutes. Spread over 43.17 acres, the park has facilities like children play area with equipments, open gym, pop up irrigation system, public convenience, different types of lights, including garden lantern, among others.

For better security of the people, it is equipped with CCTVs, the LG office said in a statement. Saxena appreciated the 'Design, Development and Maintenance' of the green area, as also the manner in which the heritage structures in the park were being maintained.

Witnessing the historical references that had been incorporated in the Landscape Design of the green area, Saxena directed officials to explore replicating the same in other parks that had heritage structures.

The LG also asked for Baradari area of monument to be explored for holding cultural events by Department of Archeology,Delhi Government with requisite safety measures.

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 22 AUGUST, 2022

VISITS 43-ACRE PARK IN VASANT VIHAR

Promote more cultural events at Vasant Udyan: L-G to DDA

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lt Governor V K Saxena on Sunday directed officials of the Delhi Development Authority to facilitate and promote more cultural events at its sprawling Vasant Udyan in south Delhi.

Saxena visited the 43-acre park in Vasant Vihar on Saturday and took stock of the development work being done there, officials said.

"Visited Vasant Udyan — Bagh e Bahar. Directed officials to facilitate and promote more cultural events in the park & encourage local artists to perform there without charging any fee. @official_dda has done a remarkable job of developing & maintaining the park," the LG tweeted.

A senior official of the DDA said, before 2018, the park was in shambles with weed overgrowth. "In 2018-2019, work was done to revamp it and by 2020 it was opened to the public again. The park which also has a monument — Bara Lao ka Gumbad — maintained by the ASI, is a very attractive destination in the city. There is also an an old well in the park," he said.

The park has landscaped design, an amphitheatre and a performing area for artistes.

"We charge Rs 5,000 for hiring the facility for one-and-a-half day, but the performing area is free for artistes," he said.

Saxena asked officials to organise more cultural events in the amphitheatre of the park, and local artistes be encouraged to perform there. He directed DDA does officials to not charge artists for using the facilities.

"Vasant Udyan park at Vasant Vihar also known as Bagh-e-Bahar, is a prestigious park of DDA with all the modern facilities. The redevelopment work of the park was completed in the year 2020. The park was selected for exhibiting at India Pavilion, London Biennale 2021, which is a global gathering of the world's most ambitious and imaginative designers, curators and design institutes," the DDA said in a statement.

Spread over 43.17 acres, the park has facilities like children play area with equipments, open gym, pop up irrigation system, public convenience, different types of lights, including garden lantern, among others. For better security of the people, it is equipped with CCTVs cameras, it said.

Witnessing the historical references that had been incorporated in the landscape design of the green area, Saxena directed officials to explore replicating the same in other parks that had heritage structures.

22 अगस्त • 2022
राष्ट्रीय सहारा

एलजी ने कलाकारों को प्रोत्साहित करने का दिया निर्देश

वीके सक्सेना ने किया वसंत उद्यान का दौरा

नई दिल्ली (एसएनबी)। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वसंत विहार में वसंत उद्यान का दौरा किया और पार्क में किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। सक्सेना ने निर्देश दिया कि पार्क के एम्फीथिएटर क्षेत्र में और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और स्थानीय कलाकारों तथा अदाकारों को पार्क में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि डीडीए इन कलाकारों से सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क वसूल न करे। वसंत विहार में वसंत उद्यान पार्क जिसे बाग-ए-बहार के नाम से भी जाना जाता है, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीडीए का एक प्रतिष्ठित पार्क है। पार्क का पुनर्विकास कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। 43.17 एकड़ में फैले हुए इस पार्क में बच्चों के खेलने को विभिन्न उपकरणों से युक्त प्ले एरिया, ओपन जिम, पॉप अप सिंचाई प्रणाली, आम जनता को सुविधा, विभिन्न प्रकार की लाइटें हैं। उपराज्यपाल ने हरित क्षेत्र के डिजाइन, विकास और रखरखाव के साथ-साथ पार्क में विरासत संरचनाओं को बनाए रखने के तरीके की भी सराहना की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक भास्कर ----------DATE नई दिल्ली, सोमवार 22 अगस्त, 2022 | 02

डीडीए बाग-ए-बहार में ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें : उपराज्यपाल

स्थानीय कलाकारों से बिना कोई शुल्क लिए उन्हें प्रोत्साहित करें अधिकारी : वीके व्यास

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वसंत विहार में वसंत उद्यान (बाग-ए-बहार) का दौरा किया और पार्क में किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। सक्सेना ने डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क के एम्फीथिएटर क्षेत्र में और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, और स्थानीय कलाकारों और कलाकारों को पार्क में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि डीडीए इन कलाकारों से सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शुल्क नहीं लेकर प्रोत्साहित करे। इस पार्क का पुनर्विकास कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। पार्क को इंडिया पवेलियन, लंदन बिएनले 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था, जो दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी और कल्पनाशील डिजाइनरों, क्यूरेटर और डिजाइन संस्थानों की वैश्विक सभा है। 43.17 एकड़ में फैले इस पार्क में बच्चों के लिए उपकरणों के साथ खेलने का क्षेत्र, ओपन जिम, पॉप अप सिंचाई प्रणाली, सार्वजनिक सुविधा, बगीचे की लालटेन सहित विभिन्न प्रकार की रोशनी जैसी सुविधाएं हैं।

इस पार्क में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उपराज्यपाल ने हरित क्षेत्र के डिजाइन, विकास और रखरखाव के साथ-साथ पार्क में विरासत संरचनाओं को बनाए रखने के तरीके की भी सराहना की।

पंजाब केसरी
DELHI

एलजी ने डीडीए को वसंत उद्यान में अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों को बढ़ावा देने का दिया निर्देश

बिना शुल्क स्थानीय कलाकारों और अदाकारों को करें प्रोत्साहित: एलजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वसंत विहार में वसंत उद्यान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके विस्तार का जायजा लेने के दौरान सक्सेना ने निर्देश दिया कि पार्क के एम्फीथिएटर क्षेत्र में और अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस दौरान स्थानीय कलाकारों तथा अदाकारों को पार्क में प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि डीडीए इन कलाकारों से सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क वसूल न करे।

बता दें कि वसंत विहार में वसंत उद्यान पार्क जिसे बाग-ए-बहार के नाम से भी जाना जाता है, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीडीए का एक प्रतिष्ठित पार्क है। पार्क का पुनर्विकास कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। पार्क को इंडिया पवेलियन, लंदन बिनाले 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था, जो दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी और कल्पनाशील डिजाइनरों, क्यूरेटरों और डिजाइन संस्थानों की वैश्विक सभा है।

वसंत विहार में वसंत उद्यान का दौरा करते एलजी विनय कुमार सक्सेना।

43 एकड़ में फैला है वसंत उद्यान पार्क

वसंत उद्यान पार्क 43.17 एकड़ में फैलेहुए इस पार्क में बच्चों के खेलने हेतु विभिन्न उपकरणों से युक्त प्ले एरिया, ओपन जिम, पॉप अप सिंचाई प्रणाली, आम जनता हेतु सुविधा, विभिन्न प्रकार की लाइटें,जिसमें बगीचे की लालटेन भी शामिल है, जैसी सुविधाएंहैं। लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए इसमें सीसीटीवी लगे हैं। इस दौरान उपराज्यपाल नेहरित क्षेत्र के डिजाइन, विकास और रखरखाव के साथ-साथ पार्क में विरासत संरचनाओं को बनाए रखने के तरीके की भी सराहना की। हरित क्षेत्र के लैंडस्केपडिजाइन में शामिल किए गए ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए, सक्सेना ने अधिकारियों को अन्य पार्कों जिनमें ऐसी विरासत संरचनाएं हैं, में भी इस पद्धति को दोहराने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने अपेक्षित सुरक्षा उपायों के साथ पुरातत्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिएस्मारक के बारादरी क्षेत्र का पता लगाने के लिए भी कहा।